

	राजस्थान राजपट्टवशेषांक साधकार मिकाशत	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary Published by Authority
	वैशाख 15, मंगलवार, शाके 1948- मई 05, 2026 Vaisakha 15, Tuesday, Saka 1948- May 05, 2026	
	भाग 4 (ग) उप-खंड (I)	

राज्य सरकार तथा अधिनियम-महाधकारयुक्तवारा जारिकये गये (सामान्य आदेश, उप-
वधयुक्त आदेश को सिद्धमलत करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

संसदिय कायबभाग

अधिसचना

जयपुर, मई 05, 2026

जी.एस.आर.12 :-राजस्थानवधान सभा (अधकारयुक्त तथा सदस्य क पारलिभधयां और पशन) अधिनियम,1956 (1957 का अधिनियम सं. 6) क धारा 4-क क उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 11 वारा मदन शिष्टतयुक्त का मयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थानवधान सभा भतपव सदस्य और कटुब पशनर (चक्र सा सवधाएं) नियम, 2010 को और संशोधन करने के लिए इसके वारा ननलखत नियम बनाती है, अथात्:-

1. संवत्त नाम और मारंभ.- (1) इन नियम का नाम राजस्थानवधान सभा भतपव सदस्य और कटुब पशनर उक्तचक्र सा सवधाएं (संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) ये तरु तु मव हंगे।

2. नियम 3 का संशोधन.- राजस्थानवधान सभा भतपव सदस्य और कटुब पशनर उक्तचक्र सा सवधाएं) नियम, 2010, जिसे इसम इसके पचात उडे त नियम के उपमननद टक्या गया है, के नियम 3 केवपयमानखंड (क) के धान पर ननलखत मपतथापतक्या जायेगा, अथात्:- "(क) 50,000/- रुपये मपतवष क अधिकतम खच सीमा तक, जिसम 5,000/- रु. मपतवष तक

आरजीएचएस के अधीन सचीबपधू जांच (पैथोलोजिकल, बैटैरियोलोजिकल, रेडियोलोजिकल और अधिनियम) सिद्धमलत ह, बाह्य उपचार के मामले म एलोपैथिक औषधयां, औषध, वेड सीन, सीरा, अधिनियम चक्र सा पदाथ आरजीएचएस के अधीन माप यता मपत फामा टोर/ई-फामा टोर सेलये जा सका गे। यद सरकार अ पताल म जांच उपलध नह है तो सरकार अ पताल से अनपलधुता ममाणपध अपेकत है:

परंतु अंतरंग रोगी को औषध, खच सीमा कावचारकये ढबना उपलध करवायी जायगी। परंतु यह औरक पशनर, जिउ हने 75 वष या अधिक क आय मपत तु कर ल है, को 3,000/- रु. मपतवष क सीमा तक ननलखत उपचार/रोग के मामले म, वटाम स, मनर स और एंट-ऑड सीडट उपलध करवाये जायगे:-

24राजस्थान राज-पट्ट, मई 05, 2026 भाग4(ग)

अंग म यारोपण (जैसेकडनी,

(i)क सर, (ii) धायी यकत रोग, (iii)कडनी फेल, (iv) मई यु

फेफड़े, यकत और अिधमां जा म यारोपण) और (v) दैकोक के पारणाम वधप पाकर सन रोग के धायी लण।

मधिकत चक्र सा पारर वारा लखे गयेवटाम स, मनर स, एंट-ऑड सीडट का संदाय आरजीएचएस दर पर फामा टोर/ई-फामा टोर कोक्या जायेगा।”

3. नियम 4 का मपतथापन.- उडे त नियम केवपयमान नियम 4 के धान पर ननलखत मपतथापतक्या जायेगा, अथात्:-

“4. नियम 3 के अधीन खच सीमा मशथलकरण.- (1) मख सचवु, नियम 3 मवपनद ट औषध के खच क सीमा समे त पा ममल ममपतवष 1,00,000/- रुपये तक और क सर, कडनी फेल और गदा उरेनल रोग के उपचार के संबंध ममपतवष 2,00,000/- रुपये क सीमा तक, ननलखत सेमलकर बनी मपत कसफारश पर और जहां आवक यक समझी जाये, दसर उक्त सीय राय ममपत त करने के पचात

आरजीएचएस पोर्टल के माँ यम से बढ़ा सकेगा, अथात्:-

1.ममख

सचवु - अँ य

2.राजध थानवधान सभा के सरकारध अध पताल

काचक× सा अधकारध

- सदध य

3.वणीय सलाहकार/मँ यु लेखा अधकारध/वरु ठ

लेखा अधकारध

- सदध य-सचव।

ऑटु पण: आरजीएचएस के अधीन सचीबपुध जांचू (पैथोलोजिकल, बैधै टैरयोलोजिकल, रेडयोलोजिकल और अँ य) के लए, मँतवष 5,000/- रु. कध खच सीमा है। सचीबपुध जांचू कध खच सीमा मँ विपुध, उप-पुनयम (1) के अधीन खच सीमा के भीतर मँमख सचव पुवारा अनमोऑदत कध पु जायेगी।

(2) समध त पाहु मामलु मँमँतवष 1,00,000/- रुपये से अधक बाधय उपचार के मामले मँ औषधु और ओषधय कध खच सीमा और मँतवष 2,00,000/- रुपये कध सीमा से अधक कध सर, कडनी फेल और गदा (रेनल) रोग के संबधत उपचार के संबध मँपुन नल खत सधम ध तर पुवारावपुनध चयकया जायेगा:-

1.चक× सा और ध वधध यवभाग पुवारा यथा मँधकत अपुतरधे तु सीईओ/संयधे तु सीईओ,

राजध थान राँ य ध वधध य बीमा एजसी (समध त पाहु मामलु मँ 1,00,000/- रुपये से अधक)

2.मँ यु कायकारध अधकारध, राजध थान राँ य ध वधध य बीमा एजसी (2,00,000/- रुपये से अधक और 7,00,000/- रुपये तक)

3.मँशासपुनकवभाग-चक× सा और ध वधध यवभाग (7,00,000/- रुपये से अधक)

ऑटु पण: आरजीएचएस के अधीन सचीबपुध जांचू (पैथोलोजिकल, बैधै टैरयोलोजिकल, रेडयोलोजिकल और अँ य) के लए खच सीमा 5,000/- रु. मँतवष है। उप-पुनयम (2) के अधीनवध तारत

भाग4(ग)राजधथान राज-पहु,मई 05 202625

खच सीमा के मामले मँ सचीबपुध जांच कध खच सीमा मँवध तार को उप-पुनयम (2) के अधीन खच सीमा मँवध तार के भीतर सीईओ, राजध थान राँ य ध वधध य बीमा एजसी पुवारा अनमोऑदतकया जायेगा।

[सं. 7(1)संसद/2021]
राँ यपाल के आदेश से,
राघवेपुहु काछवाल,
मँमख शासन सचव।

Parliamentary Affairs Department

Notification

Jaipur, May 05, 2026

G.S.R.12 .-In exercise of the powers conferred by section 11 read with sub-section (2) of section 4-A of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments and Pension) Act, 1956 (Act No. 6 of 1957), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) (Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 3.- The existing clause (a) of rule 3 of the Rajasthan Legislative Assembly Ex-Members and Family Pensioners (Medical Facilities) Rules, 2010, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-

"(a) Allopathic drugs, medicines, vaccines, sera, other therapeutic substances can be taken from pharma store/ e-pharma store recognized under the RGHS in case of outdoor treatment upto the cost ceiling of Rs. 50,000/- per annum, which includes the listed tests (pathological, bacteriological, radiological and other) under RGHS upto Rs 5000/- per annum. NAC is required from Government hospitals in case the test is not available in the Government hospitals:

Provided that medicines to the indoor patients shall be made available irrespective of the cost ceiling.

26 राजस्थान राज-पङ्क. मई 05, 2026 भाग 4 (ग)

Provided further that vitamins, minerals and anti-oxidant shall be made available upto the limit of Rs 3000/- per annum for the pensioners who have attained the age of 75 years or above in the case of following treatment/ diseases:-

(i) Cancer, (ii) Chronic Liver Disease, (iii) Kidney Failure, (iv) Major Organ Transplant (i.e. Kidney, Lungs, Liver and Bone Marrow Transplant) and (v) Strokes resulting in permanent symptom/ Parkinsons disease.

The payment of Vitamins, Minerals and Anti-oxidant prescribed by authorized medical attendant shall be made to Pharma stores/e-pharma stores on RGHS rates."

3. Substitution of rule 4.- The existing rule 4 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"4. **Relaxation in cost ceiling under rule 3.-**(1) The Principal Secretary may extend the cost ceiling for medicines specified in rule 3 upto Rs. 1,00,000/- per annum in all deserving cases and in respect of treatment of cancer, kidney failure and renal disease upto limit of Rs. 2,00,000/- per annum through RGHS portal on the recommendation of the committee consisting of the following and after obtaining second medical opinion where it is felt necessary, namely:-

1. Principal Secretary

- President

2. Medical Officer of the Government Hospital
of the Rajasthan Vidhan Sabha

- Member

3. Financial Adviser/Chief Accounts officer/
Senior Accounts officer

- Member Secretary

Note: For the listed tests (pathological, bacteriological, radiological and other) under RGHS, there is ceiling of Rs 5000/- per annum. The extension in cost ceiling of the listed tests shall be approved by the Principal Secretary within cost ceiling extended under sub-rule (1).

(2) The extension of cost ceiling of drugs and medicines in case of outdoor treatment above Rs. 1,00,000/- per annum in all deserving cases and in respect of treatment of cancer, kidney failure and renal diseases above the limit of Rs.

2,00,000/- per annum shall be decided by the following competent level:-

1. Additional CEO/Joint CEO, Rajasthan State Health Assurance Agency
as authorized by medical and health department (above Rs. 1,00,000/- in
all deserving cases)
2. Chief Executive Officer, Rajasthan State Health Assurance Agency
(above Rs. 2,00,000/- and upto Rs. 7,00,000/-)
3. Administrative Department- Medical and Health Department (above Rs.
7,00,000/-)

भाग 4(ग) राजस्थान राज-पट्ट, मई 05 2026 27

Note: For the listed tests (pathological, bacteriological, radiological and other) under RGHS, there is ceiling of Rs 5000/- per annum. In case of cost ceiling extended under sub-rule (2), the extension in the cost ceiling of the listed tests shall also be approved by the CEO, Rajasthan State Health Assurance Agency within cost ceiling extended under sub-rule (2)."

[No. 7(1) Sansad/2021]

By order of the Governor,

Raghavendra Kachawal,

Principal Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.